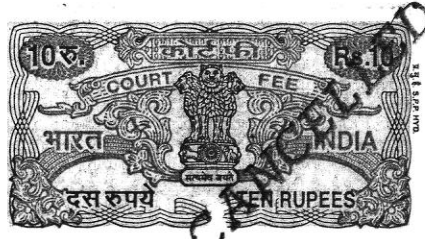


अधिकारों एवं अभिभावकों
आदि के हस्ताक्षर



8
1-1-15

R 432

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, केम्प सागर म०प्र०

श्रीमती धनियाबाई पत्नि कुवा अहिरवार

निवासी- ग्राम पाली, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर म०प्र०

..... आवेदिका.

// विरुद्ध //

नशुमा तनय कुवा अहिरवार

निवासी- ग्राम पाली, तहसील बिजावर, जिला छतरपुर म०प्र०

..... अनावेदक.

निगरानी अन्तर्गत धारा -50 म० प्र० भू-राजस्व संहिता 1959

यह निगरानी, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय सागर संभाग, सागर म०प्र० के अपील प्र०क्र०-228/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक- 22.1.2015 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों एवं आधारों पर माननीय के समक्ष प्रस्तुत है :-

॥ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ॥

1. यह कि, आवेदिका ग्राम पाली की निवासी है जहां आवेदिका के स्वामित्व, आधिपत्य की पैत्रिक भूमि खतरा नं. 303 रकबा 0.687 स्थित है, जिस पर उसका स्वामित्व व आधिपत्य है परन्तु तहसीलदार बिजावर द्वारा अपीलार्थी/आवेदिका को कोई सूचना दिए वगैर ही एकपक्षीय ढंग से प्र०क्र०- 95/अ-6अ/12-13 में दिनांक- 12.9.13 को आदेश पारित कर उक्त भूमि पर प्रतिअपी० नशुमा का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त कर दिया जिसकी कोई सूचना अपीलार्थी/आवेदिका को नहीं दी गई, ना ही उसे तर्क साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया और नशुमा चमार द्वारा अनैतिक रूप से तहसीलदार से आपसी मेलजोल कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करा लिया जिसके तत्काल अतिरिक्त न्यायालय के द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है

माननीय 4-2-15
सचिव
गोपाल

Handwritten signature



श्री संजय अहिरवार
सागर
सागर (म.प्र.)

B.O.R.

2 JAN 2015

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

व्यानियाबाई / मधुवा

प्रकरण क्रमांक. निग.प.उ.रक/२०१५ जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-2-14 सागर	<p>आवेदक (अधिवक्ता) द्वारा ग्राहपत्र पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ आति. आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय के प्र.क्र. 228/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 22-1-15 की सत्यतालिपि का अवलोकन किया गया, जिससे दुरिक्त होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- अतिरिक्त आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि उनके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि तहसीलदार बिजावर का आदेश दि. 12-9-2013, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 7-1-14 के अनुपालन में की गई कार्यवाही है। इसलिये अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से नस्तीबंद की गई है। आति. आयुक्त के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अपर न्यायालय का आदेश निम्न न्यायालय पर बंधनकारी है। अतः प्रथमदृष्टया इस निगरानी में बल नहीं होने से सुनवाई हेतु अग्रहण की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">प्रशासकीय सचिव</p>	